भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1835
दिनांक 30 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

पर्वतीय क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं

1835. श्रीतमिलसेल्वन थंगाः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बीएसएनएल के ग्राहकों की संख्या बढ़ रही है और उपभोक्ताओं के लिए इसकी लागत कम हुई है तथा देश के 99.6 प्रतिशत जिलों में रह रही 82 प्रतिशत आबादी के लिए 5जी सेवा उपलब्ध है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:

(ख) क्या बीएसएनएल ने 2007 के बाद पहली बार तिमाही लाभ अर्जित किया है/कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का देश भर में, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं में सुधार के लिए और कदम उठाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा समय-समय पर एकत्रित और प्रकाशित बीएसएनएल सहित देश भर के विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के उपभोक्ताओं का विवरण इस संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है। साथ ही, आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप, बीएसएनएल ने अखिल भारत में संस्थापना के लिए स्वदेशी रूप से विकसित 4जी साइट के लिए क्रय आदेश दिया है। 4जी उपकरणों की आपूर्ति सितंबर 2023 से शुरू हो गई है और

30.06.2025 तक कुल 95,537 4जी साइट स्थापित की गई हैं और 90,035 साइट ऑन-एयर हैं। ये उपकरण 5जी अपग्रेड करने योग्य हैं।

(ख) और **(ग)** बीएसएनएल को प्रदान किए गए पुनरूद्धार पैकेजों के परिणामस्वरूप, बीएसएनएल ने वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रचालनात्मक लाभ अर्जित करना शुरू कर दिया है और बीएसएनएल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की तीसरी और चौथी तिमाही में क्रमशः 262 करोड़ रुपये और 280 करोड़ रुपये का निवल लाभ अर्जित किया है।

(घ) और (ङ) देश भर के पहाड़ी क्षेत्रों में दूरसंचार अवसंरचना में सुधार के लिए, सरकार डिजिटल भारत निधि (पूर्ववर्ती यूएसओएफ) के तहत विभिन्न परियोजनाएं कार्यान्वित कर रही है जैसे कि (i) देश भर के सेवा से वंचित गांवों में 4जी मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए 4जी सेचुरेशन परियोजना, (ii) बीओपी/बीआईपी में 4जी आधारित मोबाइल सेवाओं के प्रावधान के लिए सीमा चौकी (बीओपी)/बार्डर इंटेलिजेंस पोस्ट (बीआईपी) परियोजना, (iii) वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने की स्कीम, (iv) आकांक्षी जिलों में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने की स्कीम, (v) सेवा से वंचित गांवों और राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे मोबाइल कवरेज प्रदान करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए व्यापक दूरसंचार विकास योजना (सीटीडीपी), और (vi) भारतनेट परियोजना जिसका चरण-वार कार्यान्वयन देश की सभी ग्राम पंचायतों और गांवों में मांग के आधार पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किया जा रहा है।

****